

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक),
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: शिविर/ 40601-40694/2023-24

दिनांक ०२ जनवरी, 2024

विषय: 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: 3023स०सु०/2023-30स०सु०/2019 दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ०प्र० व समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ०प्र० को विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त पत्र की प्रति शिविर कार्यालय को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश निर्गत किये जाय।

2- उक्त संदर्भित पत्र में मुख्य रूप से निम्न तथ्यों का उल्लेख है:-

1) डा० शुचिता चतुर्वेदी, सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के पत्र सं०-रा०बा०आ०/1595/40/विविध/2023-24 दिनांक 15.12.2023 द्वारा अवगत कराया है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएँ हो रही हैं तथा के०जी०एम०यू० व लोहिया संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त ऑकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना में जान गँवाने वाले 40 प्रतिशत नाबालिग बच्चे होते हैं, जिनकी आयु 12 से 18 वर्ष के बीच की होती है। सदस्य, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाये तथा समस्त शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी/निजी/मदरसा आदि) में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाये और मोटरयान अधिनियम-199(क)(1) के अन्तर्गत वाहन स्वामी 5(1) को उत्तरदायी ठहराते हुए कार्यवाही की जाये जिससे समाज के भावी कर्णधारों व मेधा शक्ति की अपूरणीय क्षति को रोका जा सके।

2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चलाया जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सी०सी० से कम इंजन क्षमता की मोटरसाइकिल को चला सकेगा। इसी के साथ ही धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति से न तो यान चलावाएगा और न ही इसे चलाने की अनुमति देगा, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो। उपरोक्त के अतिरिक्त मोटरवाहन संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से किशोरों द्वारा किये जाने वाले मोटर वाहन अपराधों के संबन्ध में एक नयी धारा 199क जोड़ी गयी है जिसके अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी किशोर द्वारा मोटरवाहन अपराध में किशोर के संरक्षक/मोटरवाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुए दण्डित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत संरक्षक/मोटरवाहन स्वामी को 03 वर्ष तक का कारावास तथा 25 हजार रु० तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन 01 वर्ष की अवधि के लिये निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसे किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही बन सकेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

3- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 899 राजकीय इण्टर कालेजों में रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत गतिविधियों के आयोजन हेतु धनराशि रुपये 44.95 लाख (प्रति रोड सेफ्टी क्लब रुपये 5,000.00) की बजटीय व्यवस्था कराने हेतु शिविर कार्यालय के पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 द्वारा एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2373 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की दीवारों पर यातायात नियमों/स्लोगन को लिखवाये जाने हेतु धनराशि रुपये 11,86,500/- (प्रति विद्यालय रुपये 500.00) की बजटीय व्यवस्था कराने हेतु शिविर कार्यालय के पत्र दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के उक्त संदर्भित पत्र में की गयी अपेक्षानुसार 18 वर्ष से कम आयु के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं उक्त के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में, अपने जनपद के सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन)/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) से समन्वय स्थापित करते हुए उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,

डॉ०(महेन्द्र देव)

शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)

उ०प्र०, लखनऊ।

पृ०सं०: शिविर/

/2023-24, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक समस्त मण्डल, उ०प्र०।